रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 1999/अग्रहायण 9, 1921
No. 265] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 1999/AGRAHAYANA 9, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1999

फा. सं. 31/11/99-वि.क.—सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 16 नवम्बर, 1999 को हुए मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में संकल्प लिया गया था जिसमें सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की जांच करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक स्थाई समिति का गठन करने की सिफारिश की गयी थी।

2. इस संकल्प के अनुसरण में, सरकार ने इसके प्रयोजनार्थ एक स्थायी समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. गुजरात के वित्तमंत्री	—सदस्य
2. कर्नाटक के वित्तमंत्री	—सदस्य
3. मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री	—सदस्य
4. महाराष्ट्र के वित्तमंत्री	—सदस्य
5. पंजाब के वित्तमंत्री	—सदस्य
6. उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री	—सदस्य
7. पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री	—संयोजक सदस्य

3. डा. महेश सी. पुरोहित, प्रोफेसर एनआईपीएफ एण्ड पी, नई दिल्ली समिति के सचिव होंगे।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) राज्यों तथा संघ शासित राज्यों द्वारा बिक्री कर की एक-समान दरों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना जिन्हें 1-1-2000 से लागू करने का निर्णय लिया गया था।

(ii) 1-1-2000 से बिक्री का आधारित प्रोत्साहन स्कीमों को समाप्त करने पर निगरानी रखना।

(iii) 1-4-2001 से राज्य सरकारों द्वारा वीएटी को लागू करने के लिए उसके तरीकों और प्रारंभिक कार्य पर निगरानी रखना।

5. समिति अपने कार्य के लिए स्वयं की कार्य-पद्धति तैयार करेगी, यह केन्द्र सरकार तथा राज्य/संघ शासित सरकारों से जरूरत होने पर सूचना मांग सकती है।

6. एन. आई. पी. एफ. एंड पी., नई दिल्ली, समिति को सचिवालीय सहायता प्रदान करेगा।

जी. सी. श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th November, 1999

F. No. 31/11/99-ST.—The Conference of Chief Ministers and Finance Ministers of all States/Union Territories held on 16th November, 1999 had adopted a resolution recommending Constitution of a Standing Committee of State Finance Ministers to monitor the decisions taken in the Conference.

2. In pursuance of this Resolution, the Government has decided to appoint a Standing Committee for this purpose. It will consist of : -

1. Finance Minister of Gujarat	—Member
2. Finance Minister of Karnataka	—Member
3. Finance Minister of Madhya Pradesh	—Member
4. Finance Minister of Maharashtra	—Member
5. Finance Minister of Punjab	—Member
6. Finance Minister of Uttar Pradesh	—Member
7. Finance Minister of West Bengal	—Convenor Member

3. Dr. Mahesh C. Purohit, Professor, National Institute of Public Finance and Policy will be Secretary of the Committee.

4. The terms of reference of the Committee will be : —

(i) To monitor the implementation of uniform floor rates of salex-tax by States and Union Territories which was decided to be implemented with effect from 1-1-2000.

(ii) To monitor the phasing out of the sales-tax based incentive schemes with effect from 1-1-2000.

(iii) To monitor the modalities and preparatory work for introduction of VAT by State Governments with effect from 1-4-2001.

5. The Committee will evolve its own procedure for its work and may call for information as may be necessary from Central and State Government/Union Territories.

6. The National Institute of Public Finance and Policy will provide secretarial assistance to the Committee.

DR. G.C. SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054